नई दिल्ली के ललित होटल में शनिवार शाम आयोजित 'हिन्दुस्तान कान्क्लेव' में शिक्षा जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की। इन हस्तियों ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं की भूमिका को अहम बताया और इस दिशा में सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया। • अरुण कुमार

केएन मोदी फाउंडेशन के ट्रस्टी संजय गुप्ता (बाएं) को हिन्दुस्तान की ओर सम्मानित किया गया।

शोध, इनोवेशन में निजी संस्थाएं आगे आएं

वक्त कोई भी हो, भारत शिक्षा की लौ जला दुनिया को पाठ पढ़ाता रहा है। चाहे प्रख्यात गणितज्ञ आर्यभट्ट के जीरो का आविष्कार हो या विश्वप्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की गुरुकुल परंपरा। देश ने डंका कायम रखा है। समय बदला, तकनीक आई। आईआईटी व आईआईएम जैसे संस्थानों के साथ निजी क्षेत्र ने शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर को बनाए रखने का जिम्मा संभाला लेकिन तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ते हिन्दुस्तान के सामने चुनौतियां भी हैं। आज के दौर में निजी संस्थानों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है और यहां कितने अवसर हैं, इन तमाम पहलुओं पर हिन्दुस्तान ने कान्क्लेव आयोजित किया। जहां शिक्षाविदों ने मंथन कर कहा 'निजी संस्थानों को इनोवेशन के लिए आगे आना चाहिए।' पेश है 'हिन्दुस्तान' की खास रिपोर्ट

चुनौतियों के बावजूद लगातार शिक्षित होते हिन्दुस्तान के लिए शनिवार की शाम बेहद खास रही। 'हिन्दुस्तान' ने ललित होटल में 'शिक्षा में निजी क्षेत्र के योगदान' पर कान्क्लेव आयोजित किया, जहां देश की नामचीन हस्तियों ने नए नजरिये के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका को अहम बताते हुए कहा, 'निजी संस्थानों को चुनौतियों से निपटने के लिए काम करना चाहिए और शोध व इनोवेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए।'

कार्यक्रम की खास बात यह रही कि यहां मंथन के लिए सरकारी मशीनरी से जुड़े शिक्षाविदों से लेकर निजी क्षेत्र के नुमाइंदे भी पहुंचे। इन छह पैनलिस्ट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निदेशक विक्रम सहाय, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के चेयरमैन डॉ. एसएस मंथा, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा) मधुरानी तेवतिया थीं। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों से रेयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीईओ रेयान पिंटो, शारदा यूनिवर्सिटी के चांसलर विजय गुप्ता और वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉ. नरेंद्र सिंह भी बतौर पैनलिस्ट मौजूद थे।

यूजीसी निदेशक विक्रम सहाय ने उच्च शिक्षा पर कहा कि निजी संस्थाएं काम कर रही हैं लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। सरकारी व्यवस्था संग इन्हें काम करना चाहिए। दोनों की कोशिशों से सकारात्मक बदलाव आएगा।

विशेषज्ञों से पूछे सवाल: कान्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेजों के चेयरमैन व प्रिंसिपल भी पहुंचे। इन्होंने वाकायदा पैनलिस्ट से सवाल पूछे। किसी ने निजी निवेश में आने वाली अड़चनों पर सवाल पूछा तो किसी ने सवाल किया कि क्या यूजीसी को निजी क्षेत्रों को आर्थिक मदद नहीं देनी चाहिए? इस पर यूजीसी निदेशक ने कहा कि हम व्यवस्था को बनाए रखते हैं। सरकार सीधे तौर पर निजी संस्थाओं को पैसा नहीं देती लेकिन उनके छात्रों के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप जरूर दी जाती हैं।

WORLD COLLEGE
OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
FARUKHNAGAR, GURGAON
Courses Offered
B.TECH | M.TECH | BBA
MBA | PGDM | BCA
MCA | B.ED
www.wctmgurgaon.com
Ph.: 08800212216 / 75, 09717964085

RYAN
RYAN INTERNATIONAL
GROUP OF INSTITUTIONS
India's Best Schools

Announces
Admission 2014
Dr. K.N. Modi Foundation
DR. K.N. MODI UNIVERSITY
Modinagar (U.P.): 08859500790/91/92/93
Newai (Raj.): 08875010001/02/03/04/05
Delhi: 09910003701/02, 011-41034516.

हिन्दुस्तान कान्क्लेव में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से आए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

इन प्रतिनिधियों ने पैनलिस्ट से निजी निवेश और नियमों से जुड़े कई सवाल भी पूछे। • अरुण कुमार

विक्रम सहाय, निदेशक, यूजीसी

वोकेशनल शिक्षा और शोध को दें बढ़ावा

देश में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। 723 विश्वविद्यालय हैं। 23 फीसदी निजी है। 37204 कॉलेजों में 60 फीसदी निजी संस्थाएं हैं। इससे पता चलता है कि हिन्दुस्तान में निजी संस्थाएं उच्च शिक्षा की दिशा में कदम रख रही हैं। लेकिन इन निजी संस्थाओं को वोकेशनल पढ़ाई, शोध और इनोवेशन पर जोर देना होगा। अहम बात यह है कि योगदान लाभ के लिए नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हो। तभी निजी क्षेत्र शिक्षा में सही मायने में योगदान दे सकेगा।

मेरा मानना है कि निजी क्षेत्र को उच्च शिक्षा में बेहतर करने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ काम करना चाहिए। इससे छात्रों के पास विकल्प ज्यादा होंगे। निजी निवेश सिर्फ रोजगारपरक कोर्स उपलब्ध कराने के लिए ही नहीं होना चाहिए बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व के विकास से संबंधी कोर्स के लिए भी होना चाहिए। बहरहाल, अवसर शिक्षा की जब भी बात आती है तो सरकार बनाम निजी क्षेत्र हो जाता है। ऐसा सोचना सही नहीं है। शिक्षा के लिए दोनों को साथ देखना होगा। यह आज की मांग है। अंत में यही कहूंगा कि हमारे देश के छात्रों का भविष्य उज्जवल है क्योंकि यहां शिक्षा और प्रतिभा की कमी नहीं है।

डॉ. एसएस मंथा, चेयरमैन, एआईसीटीई

उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने में भूमिका अहम

देश में करीब 12 हजार पेशेवर कॉलेज हैं। यहां तक सिर्फ ढाई करोड़ छात्र पहुंच पाते हैं, जबकि पांच करोड़ छात्र 12वीं पास कर रहे हैं। तस्वीर साफ है। 12वीं पास करने वाले आधे छात्र ही उच्च शिक्षा की ओर बढ़ पाते हैं। इस खाई को मिटाना होगा। मैं बताना चाहूंगा कि अभी उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन बेहद कम है। अभी औसतन नामांकन 18 फीसदी है। 2020 तक 30 फीसदी तक पहुंचने का लक्ष्य है। सरकार और निजी क्षेत्र की कोशिशों से इस लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा।

जहां तक बात गुणवत्ता की है तो इस दिशा में निजी संस्थाओं को काम करना चाहिए। गुणवत्ता से ही वह शिक्षा के लिए अव्वल कर सकते हैं। उनका प्रदर्शन इसी पर टिका है। बहरहाल, चुनौतियां कम नहीं। हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज होने चाहिए। आबादी के हिसाब से संख्या हो। मैंने देखा है कि हिन्दुस्तान में 200 जिले ऐसे हैं जहां एक भी तकनीकी व पेशवर कॉलेज नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में 500 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इससे पता चलता है कि कई खामियां भी हैं। निजी क्षेत्र को निवेश करते समय इलाके की जरूरतों का ध्यान रखना होगा। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए सरकार के साथ निजी संस्थाओं को आगे आना चाहिए।

मधुरानी तेवतिया, अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा)

सरकार के साथ तकनीक में कर सकते हैं बेहतर

मेरे हिसाब से समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को योगदान देने के तौर पर काम करना चाहिए। संस्थाएं ऐसा कर भी रही हैं। इनकी जरूरत को नकारा नहीं जा सकता। कई बार सरकारी व्यवस्था की कुछ सीमाएं होती हैं। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र को सरकारी व्यवस्था के साथ शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। जहां तक बात तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की है तो मेरा अनुभव रहा है कि निजी कॉलेज भी तकनीक के मामले में काम कर रहे हैं। छात्रों के लिहाज यह अच्छा है।

बतौर अतिरिक्त निदेशक दिल्ली में मेरे कई अनुभव रहे। राजधानी में सरकारी स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूल अधिक है। करीब 60 फीसदी निजी स्कूल हैं। इन स्कूलों में शिक्षा का अधिकार के तहत हमनें 25 हजार बच्चों को दाखिला दिलाया है। दरअसल, यह एक उदाहरण है। इससे पता चलता है कि शिक्षा के लिए सरकार व निजी क्षेत्र मिलकर बेहतर कर रहे है और भी कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के जरिये इसी तरह निजी कॉलेजों व स्कूलों को आगे आकर छात्रों को शिक्षित करना चाहिए। निजी क्षेत्र को भूमिका तय करनी होगी। उनकी भूमिका देश का भविष्य तैयार करने के लिए होनी चाहिए।

रेयान पिंटो, सीईओ, रेयान इंटरनेशनल ग्रुप

शिक्षा की चुनौतियों से निपटा जा सकता है

देश में भले ही शिक्षा की तस्वीर पहले के मुकाबले अच्छी हुई हो लेकिन यह भी सच है कि अगले दस सालों में छह लाख शिक्षकों की जरूरत होगी। 34 करोड़ 70 लाख छात्रों को स्कूलों में होना चाहिए जबकि 23 करोड़ 70 लाख छात्र ही स्कूल जा रहे हैं। निजी संस्थाओं की मदद से ही इस अंतर को दूर किया जा सकता है। हम इसी मकसद के साथ काम कर रहे हैं।

प्रौद्योगिकी भी हिन्दुस्तान के युवाओं को आगे ले जा रही है। हमारा जोर ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने पर है जो देश के छात्रों को सिर्फ नौकरियां ही नहीं दे सके बल्कि दुनिया के सामने आत्मविश्वास से खड़ा करे। दरअसल, बाजार की बदलती जरूरतों के हिसाब से शिक्षा देनी होगी। तकनीक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। निजी क्षेत्र इसी सोच के साथ आगे आ रहे हैं लेकिन कई अड़चनें भी आती हैं। ये तकनीकी अड़चनें हैं। जब कोई शिक्षा में निवेश करता है तो उसे नियमों का पालन करना होता है जो कि सही है मगर निवेशकों के निवेश संबंधी सारे काम एक विंडो में क्लियर हो जाए तो बेहतर होगा। इससे निजी क्षेत्र और भी ज्यादा योगदान देगा। सरकारी व्यवस्था को सुविधाएं देनी चाहिए।

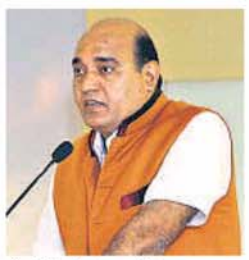

डॉ. नरेंद्र सिंह, चेयरमैन, डब्ल्यूसीटीएम

सुविधाएं देकर निजी संस्थाओं को गाइड करें

हमारे देश में शिक्षा का बहुत बड़ा तंत्र है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए सरकारी विभाग व एजेंसियां हैं। इनमें यूजीसी, विभिन्न बोर्ड व एआईसीटीई शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थाएं हैं। सभी शिक्षा के लिए काम करते हैं लेकिन सरकारी एजेंसियों को बेहतर परिणाम के लिए निजी संस्थाओं को सुविधाएं देनी होंगी। उन्हें गाइड करना चाहिए।

इस तरह साथ मिलकर काम करना होगा। जहां तक बात मौजूदा स्थिति और चुनौतियों की है तो मैं बता दूं कि आज निजी संस्थाओं की बदौलत छात्रों के पास विकल्प है। कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुणवत्ता देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे लिए ये सब बेहद चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौतियों और अड़चनों को सरकारी एजेंसियों को समझना चाहिए ताकि रुकावटें न आएं। बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए। कॉलेज में दाखिला लेना वाला हर छात्र सुविधा चाहता है। वो चाहता है कि उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा युक्त शिक्षा मिल सके। आखिर में इतना ही कहूंगा कि भारत में अमेरिका व यूरोपीय देशों को टक्कर देने की संभावना है। बशर्ते हमारी कोशिश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हो। निजी संस्थाओं को भी ध्यान रखना होगा कि गुणवत्ता के बिना वे अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे।

विजय गुप्ता, वांसलर, शारदा यूनिवर्सिटी

निजी शिक्षण संस्थाएं मौजूदा दौर की जरूरत

निजी संस्थाओं की मांग को नकारा नहीं जा सकता। ये आज की जरूरत बन गई हैं। न सिर्फ उच्च शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र काम कर रहा है। देश में उच्च शिक्षा से संबंधित यूजीसी व एआईसीटीई जैसी संस्थाएं हैं। ये हमेशा शोध की बात करती रही हैं। मेरा मानना है कि देश में नए आइडिए और उन पर काम करना सिर्फ सरकारी संस्थाओं का जिम्मा नहीं बल्कि निजी संस्थाओं का भी है। सरकारी संस्थाओं को इस बाबत निजी शिक्षण संस्थाओं को सहयोग करना होगा ताकि बेहतर परिणाम निकल सके।

देश में इंजीनियरिंग के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी है लेकिन 121 करोड़ों की आबादी वाले इस देश में इंजीनियरिंग करने की चाह रखने वाला हर छात्र आईआईटी में नहीं जा सकता, क्योंकि सीटें सीमित हैं। ऐसे में निजी संस्थाएं आईआईटी की तर्ज पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रही है ताकि छात्रों को ठीक वैसी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा युक्त शिक्षा मिल सके। आखिर में इतना ही कहूंगा कि भारत में अमेरिका व यूरोपीय देशों को टक्कर देने की संभावना है। बशर्ते हमारी कोशिश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हो। निजी संस्थाओं को भी ध्यान रखना होगा कि गुणवत्ता के बिना वे अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे।